की क्रम संख्या के अनुसार प्रतीक्षारत आवेदकों को नए एल०पी०जी० कनेक्शन जारी किए जाते हैं। अधिक से अधिक आवेदकों को यथाशीघ्र एल०पी०जी० कनेक्शन जारी करने के लिए प्रयास निरन्तर जारी हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वर्तमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता को बढ़ाकर, नए संयंत्रों की स्थापना और आयातों के माध्यम से आपूर्ति को बढ़ाकर भी और अधिक एल०पी०जी० उपलब्धता के लिए योजना बनाई जा रही है।

विवरण

क्रम संख्या	नगर/कस्बा	31.12.89 तक प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बारवानी	630
2.	भिंड	470
3.	भोपाल	5375
4.	बुरहानपुर	3015
5.	छतरपुर	2135
6.	दमोह	1140
7.	दतिया	266
8.	देवास	1723
9.	गंजबसोडा	4357
10.	गुना	464
11.	ग्वालियर	14099
12.	इन्दौर	36276
13.	जबलपुर	10076
14.	मंदसौर	5692
15.	नागदा	517
16.	नीमच	4278
17.	रतलाम	13141
18.	सागर	11732
19.	सनावाड	1076
20.	श्योपुरकलां	1839
21.	शिवपुरी	2097
22.	उज्जैन	17493
23.	रायपुर	1810
24.	भिलाई	9429
25.	सतना	1474
26.	कोरबा	3343
27.	पत्ना	1596
28.	रीवा	4143
29.	बस्तर	3504
30.	हर्दा	1620
31.	इटारसी	1200
32.	बेतुल	780
33.	सिहोर	1500
34.	बीना	1000
35.	बालाघाट	1500
36.	झालमा	4950
37.	पिथामपुर	300
38.	महिउ	110
39.	राजगढ़	1200
40.	शाहडोल	3800
41.	सुरखम	850
42.	कटनी	3920
43.	छिंदवाड़ा	2300
44.	जगदलपुर	1909
45.	दुर्ग	813
46.	रायगढ़	782
47.	भिलाई	1900
48.	नरसिंहपुर	2500
49.	टीकमगढ़	2200
50.	खारगोन	850
51.	शाजापुर	1800
52.	मोरना	517
53.	धार	3743

Setting up of a short path distillation unit at Digboi

2533. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether a Short Path Distillation Unit is to be put at Digboi in Assam at Assam Oil Division, in collaboration with the Indian Oil Corporation; and

(b) if so, the details of the project, including as to whether an assessment, of the project was made through any independent agency, whether it has been ascertained that end-use industries are available in market; whether foreign expert opinion was obtained as to the success of similar technology in other countries; and the total amount to be invested by Central and State Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA) : (a) and (b) A proposal for installation of a pilot plant for Short Path

Distillation at Digboi has been appraised by the Scientific Advisory Committee of the Ministry of Petroleum and Natural Gas. The proposal is in feasibility stage.

Strike by employees of BPCL and HPCL

2534. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of Bharat Petroleum Corporation Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited Bombay went on a day's strike on 21st February, 1995;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps have been taken by Government to redress their grievances and to resolve the issues involved?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA) : (a) to (c) All the unions representing marketing workmen in Bharat Petroleum Corpn. Ltd. (BPCL) served strike notices for early finalisation of Long-Term wage settlement and promotion Policy. Similarly, some of the unions of Hindustan Petroleum Corpn. Ltd. (HPCL), except, South Zone and Visakh Refinery, issued strike notices dated 1st February, 1995 demanding delinking of productivity in Long-Term settlement. Inspite of conciliation meetings by the Dy. Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi, the workmen went on one day strike on 21-2-95. During the strike uninterrupted supplies were maintained with the help of Officer.

As a result of conciliation and bipartite discussions in both the corporations, the workmen have since resumed normal duties. BPCL has signed a Memorandum of understanding with 12 out of 14 unions on All India basis.

गैस अॅथारिटी आॅफ इंडिया लिमिटेड का कार्य-निष्पादन

2535. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अॅथारिटी आॅफ इंडिया लि॰ की स्थापना प्राकृतिक गैस के उत्पादन के पश्चात् के कार्यों में सुधार लाने तथा उन्हें नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1994 तक इस संगठन में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संगठन को शुद्ध लाभ के रूप में कितनी औसत वार्षिक कमाई हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गैस अॅथारिटी आॅफ इंडिया लि॰ द्वारा देश की विद्युत और उर्वरक परियोजनाओं को बेहतर गुणवत्ता वाली गैस की आपूर्ति की जा रही है जिसका इन परियोजनाओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और आवश्यकतानुसार बेहतर गुणवत्ता वाली गैस की आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) गेल की स्थापना प्राकृतिक गैस के परिवहन, उपचार, संसाधन, प्रभाजन, वितरण और विपणन के मुख्य उद्देश्यों के लिए की गई थी।

(ख) 01.04.94 की स्थिति के अनुसार चुकता पूंजी 845.32 करोड़ रुपए है। पिछले तीन वर्षों में कर पश्चात् निवल लाभ निम्नवत् था :

1991-92	—	93.55 करोड़ रुपए
1992-93	—	210.53 करोड़ रुपए
1993-94	—	320.54 करोड़ रुपए

(ग) और (घ) विद्युत और उर्वरक परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति से पूर्व जहां व्यवहार्य हो, वहां एल॰पी॰जी॰, सी 2/सी 3 आदि जैसे उच्चतर प्रेरणान निकाले जाते हैं। कुछ और निकर्षण संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।